



जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Bhagwan
Ka Plot

"If there is any religious structure in the middle of the road, be it gurudwara or dargah or temple, it cannot obstruct public." (Justice B.R. Gavai, Supreme Court of India, 2024)

Chilika Turns
Pink Again

Bringing the
Mountains and the
Winter Chill to Jaipur!

टैक्सस में विशाल ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे अंबानी

CMYK

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी का प्रस्तावित दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत-अमेरिका सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। वॉशिंगटन जहां ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और वाणिज्यिक निवेश बढ़ाना चाहता है, वहीं वह रूसी तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली पर दबाव भी बना रहा है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के नए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ, आन्वजन तथा प्रौद्योगिकी बाजार तक पहुंच को लेकर उनके बीच मतभेद भी बढ़ रहे हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, रुबियो 17 से 22 अक्टूबर के बीच मुंबई और जामनगर का दौरा करेंगे। इस साल भारत की यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। इस दौरान वे वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों और कारोबारी नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। इनका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना, ऊर्जा सहयोग का विस्तार करना और निवेश के अवसर तलाशना है।

जामनगर का चयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गुजरात के इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन परिसर है, जिसे रिलायंस संचालित करती है। कंपनी अमेरिका फर्स्ट

यह गत 50 सालों में अमेरिका में बनने वाली सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी

- अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इसी सिलसिले में जामनगर आ रहे हैं और यहाँ वे अंबानी से वार्ता करेंगे।
- चर्चा है कि रिलायंस कंपनी, अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग कंपनी के साथ मिल कर टैक्सस के ब्राउन्सविल में विशाल रिफाइनरी लगा रही है।
- इससे न केवल अंबानी का दुनिया भर में रूतबा बढ़ेगा, बल्कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी महत्पूर्ण है, क्योंकि उनके कार्यकाल में अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगेगी, यह उनकी ऊर्जा नीति की बड़ी उपलब्धि साबित होगी।

रिफाइनिंग के साथ साझेदारी में टैक्सस के ब्राउन्सविल में प्रस्तावित रिफाइनरी में निवेश की योजना भी बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस परियोजना को पिछले 50 वर्षों में अमेरिका में बनने वाली पहली बड़ी नई तेल रिफाइनरी बताया है। इसलिए यह उनकी ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रस्तावित निवेश से वॉशिंगटन को रिलायंस के साथ व्यावसायिक संबंध गहरे करने का व्यवसायिक प्रोत्साहन मिलेगा। रिलायंस भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। ट्रंप प्रशासन के लिए यह परियोजना घरेलू स्तर पर ईंधन प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, विदेशी पूंजी आकर्षित करने और

यह दिखाने का अवसर हो सकती है कि भारत के साथ व्यावसायिक साझेदारी से ठोस आर्थिक लाभ हासिल किए जा सकते हैं।

नई दिल्ली के लिए ऊर्जा क्षेत्र में करीबी सहयोग, व्यापार और भू-राजनीति को लेकर मतभेद बने रहने के बावजूद, वॉशिंगटन के साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखने में मददगार हो सकता है। हालांकि, रिफाइनरी परियोजना का लंबा विकास इतिहास और फाइनैस से जुड़ी चुनौतियां बताती हैं कि इसके क्रियाव्ययन को आसान नहीं समझना चाहिए।

तत्काल कूटनीतिक चुनौती भारत की रूसी तेल खरीद के भविष्य को लेकर है। वॉशिंगटन ने रूसी ऊर्जा खरीद

जारी रखने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने की धमकी दी है। इससे नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा, आयात लागत और घरेलू ईंधन आपूर्ति की स्थिरता पर संभावित असर को लेकर चिंता बढ़ी है।

भारत यह तर्क दे सकता है कि ऊर्जा खरीद से जुड़े फैसले राष्ट्रीय जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। दंडात्मक टैरिफ के जरिए तेल आपूर्ति सीमित करने की किसी भी कोशिश से द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जटिल हो सकती है और भारतीय रिफाइनरियों तथा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। रुबियो का दौरा ऐसे समय भी हो रहा है, जब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पानी की बोतल पर 2 रूपए ज्यादा लेना महंगा पड़ा

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। पानी की एक बोतल के लिए महज 2 रुपये अतिरिक्त वसूलना उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित एक रेस्टोरेंट को महंगा पड़ गया। अलीगढ़ के जिला उपभोक्ता आयोग ने बीबीसीएन रॉयल रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल

- यूपी में हाथरस के एक रेस्त्रां पर ग्राहक से पानी की बोतल पर 2 रूपए ज्यादा लेने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया तथा ग्राहक को एक हजार रूपए हर्जाना व 5,000 रूपए कानूनी खर्च के लिए देने का आदेश भी दिया।

पर बोतल की मैकिज़मम रिटेल प्राइस (एमआरपी) से ज्यादा दाम वसूलने के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने रेस्टोरेंट को शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये मुआवजा और कानूनी खर्च के रूप में 5,000 रुपये देने का भी आदेश दिया है।

यह घटना 11 मार्च, 2026 की है, जब अलीगढ़ निवासी अंकुर अग्रवाल भोजन करने के लिए हाथरस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘धर्म परिवर्तन करने पर जातिगत आरक्षण नहीं मिलेगा’

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि हिंदू सिख व बौद्ध धर्म मानने वालों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए, फैसला सुनाया कि हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोगों को जाति आधारित रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत मिलने वाले आरक्षण का दावा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति पहले हिंदू धर्म में था और उस समय उसे सामाजिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता था। गैर-हिंदू धर्म अपनाने के बाद, वह इस आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “पहले की सामाजिक व्यवस्था में झेले गए पिछड़ेपन के आधार पर किसी व्यक्ति को उस धर्म में पिछड़े वर्ग का दर्जा नहीं

- यह विवाद तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के एक सरकारी आदेश से जुड़ा है, जिसमें पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान था, जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है।
- पर, मद्रास हाई कोर्ट ने इस सरकारी आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ईसाई और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में जाति व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये धर्म अपनाने वाले हिंदू के रूप में अपनी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं।

दिया जा सकता, जिसे उसने धर्म परिवर्तन के बाद अपनाया है। पीठ ने आगे कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 के अनुसार, अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं।

यह विवाद तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 को जारी एक सरकारी आदेश से जुड़ा है। इस सरकारी आदेश

के तहत पिछड़े वर्ग (बैकवर्ड क्लास), अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदायों या अनुसूचित जाति से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को मुस्लिम समुदाय के सात मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गों में से किसी एक का सामुदायिक प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी गई थी। इनमें “मुस्लिम लेब्बाई” समुदाय भी शामिल था।

अपने बचाव में राज्य सरकार ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य धर्म (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस साल के अंत तक शुरु हो जाएगी मुंबई मेट्रो

एलस्टॉम इंडिया के संयंत्र में 6 डिब्बों वाली प्रोटोटाइप मेट्रो रेल का अनावरण हुआ

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। मुंबई में नई मेट्रो लाइन को साल के अंत तक आंशिक रूप से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को एलस्टॉम इंडिया के श्री सिटी स्थित संयंत्र में लाइन 4 (जिसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है) और लाइन 4ए के लिए छह डिब्बों वाली पहली प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन को आंच किया गया। इस अवसर पर लार्सन एंड टुब्रो के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये दोनों लाइनें वडाला-घाटकोपर-ठाणे-गादमुख के लगभग 35 किलोमीटर लंबे मार्ग को कवर करेंगी। इन लाइनों पर अगस्त 2027 तक पूरी तरह से व्यावसायिक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

यमन राष्ट्रपति भवन पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागीं

अदन, 15 अक्टूबर। यमन की अंतरिम राजधानी अदन में हूती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन परिसर पर कई मिसाइलें दागीं। हमले में चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिनमें दो सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। समाचार

- हमले के समय प्रधानमंत्री व कई मंत्री राष्ट्रपति भवन परिसर में थे।

एजेंसी “रॉयटर्स” ने यमन के सूचना मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी। हमले के समय सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री परिसर में मौजूद थे। लेकिन सरकार के शीर्ष अधिकारी इस हमले में बाल-बाल बच गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शहर में सरकारी महल के पास कम से कम छह धमाके हुए। इस महल का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एलस्टॉम इंडिया कंपनी मुंबई मेट्रो के लिए लार्सन एण्ड टुब्रो को 39 ड्राइवर लैस मेट्रो ट्रेनें उपलब्ध कराएगी और सिग्नल सिस्टम, डिपो से जुड़े उपकरणों की देखी और 5 साल तक इनका रख रखाव भी करेगी।

एलस्टॉम इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो को बिना चालक चलने वाली (ड्राइवरलैस) 39 मेट्रो ट्रेनें उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, कंपनी सिग्नलिंग प्रणाली, डिपो से जुड़े उपकरण और पांच साल तक रखरखाव की सुविधा भी देगी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने लाइन 4 और लाइन 4ए के लिए एकीकृत प्रणाली उपलब्ध कराने का ठेका लार्सन एंड टुब्रो को दिया था। एलस्टॉम जुलाई 2027 तक मुंबई

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), जो इन लाइनों का संचालन करेगा, को छह डिब्बों वाली 39 ट्रेनें, यानी कुल 234 डिब्बे बनाकर उपलब्ध कराएगी।

रिकॉर्ड 14 महीनों में तैयारी की गई इन नई ट्रेनों को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। यात्रियों को अधिक आराम देने के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत सरकार ने दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि कॉल करने वाले का नम्बर और नाम यूजर के फोन को स्क्रीन पर दिखाई दे।

आपके फोन पर कॉल आया, तो स्क्रीन पर डिफॉल्ट रूप से कॉल करने वाले का नंबर और नाम दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने टैलिकॉम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर सख्ती का कोई खेद नहीं

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए होते तो राजधानी में कानून व्यवस्था बिगड़ जाती

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सत्तारूढ़ दल की मौजूदा सोच को दर्शाते हुए, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पुलिस ने समय पर, उचित और कानून-सम्मत कदम उठाए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में 10 अक्टूबर को काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की बड़ी समस्या को टाला जा सका।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किये गये एक हलफनामे में कुमार ने अदालत की अवमानना के एक मामले में बिना किसी शर्त के और पूरी तरह माफी मांगी। यह मामला विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाने के अदालत के निर्देश

- दिल्ली पुलिस ने रेल व मेट्रो नहीं रोके जाने के अदालती आदेश की अवमानना याचिका पर जवाब पेश करते हुए रेल व मेट्रो पर रोक लगाने के लिए माफी मांगी, पर कहा कि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी था।
- पुलिस ने कहा कि इस वजह से 10 अक्टूबर को काँकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हालात सामान्य रह पाए।
- पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने कहा, पुलिस के वास्तविक प्रयासों के बाद भी गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है।

के कथित उल्लंघन से जुड़ा था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हलफनामा पुलिस द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और प्रदर्शनकारियों के साथ

कथित सख्ती के आरोपों के जवाब में दी गई एक सामान्य प्रतिक्रिया है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि 10 अक्टूबर को उठाए गए एहतियाती कदम

खुफिया जानकारी और मौके की मौजूदा तथा लगातार बदलती स्थिति के आकलन पर आधारित थे। उन्होंने दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाओं को नियंत्रित करने सहित, पुलिस प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, “इन उपायों का उद्देश्य शांति बनाए रखना और राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना था।”

कुमार ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की स्थिति से जुड़ी कुछ खास संवेदनशीलताएं हैं।

हलफनामे में कहा गया, “कोई भी पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था का उल्लंघन होने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आमिर खान के भांजे इमरान को भारत छोड़ने का नोटिस

मुंबई, 15 अक्टूबर। बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। उन पर मुंबई में मुख्य

- अमेरिकी नागरिक होते हुए इमरान ने मुंबई में चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया।

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। यह प्रदर्शन काँकरोच जनता पार्टी के आव्हान पर किया गया था। इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल होकर इमरान खान ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)